RECOVERY OF BOMBS AND SMALL ARMS IN A RAILWAY WAGON NEAR GOVINDPUR COAL MINES, BIHAR

6366. Shri Beni Shanker Sharma : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some bombs and other small arms in 21 boxes were found in a Railway Wagon near Govindpur Coal Mines in Bihar ; and

(b) whether any investigation has been made into it and, if so, with what result ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. On 24th March, 1970, a wagon received as empty at Katrasgarh station and placed for loading coal at Tentulia Colliery Siding, when opened, was found to contain 21 cases of military explosives of which one was noticed to have been tampered with.

(b) The matter was reported to the Police Station/Katrasgarh and is under investigation.

NORMS FOR ESTABLISHING INDUSTRIES RECOMMENDED BY PANDE AND WANCHOO COMMITTEES

6367. Shri Beni Shanker Sharma : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Pande and Wanchoo Committees have recommended certain norms for establishing industries all over the country ;

(b) whether there have been complaints that the Centre has not been following the same and, if so, the details thereof ; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The Pande Working Group and the Wanchoo Working Group were not appointed to lay down any norms for establishing industries all over the country. The former was appointed to suggest criteria for the identification of backward areas and the latter to suggest fiscal and financial incentives for starting industries in backward areas.

(b) and (c). Do not arise.

12.30 Hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PROTEST BY FEDERATION OF ALL INDIA FOODGRAIN DEALERS ASSOCIATINOS AGAINST MOVE TO NATIONALISE WHOLESALE TRADE IN FOODGRAINS

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव का अखिल भारतीय अनाज विक्रेता संस्था संघ द्वारा विरोध किये जाने के समाचार"

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Anna sahib Shinde) : Government have seen newspaper reports of the proceedings of the convention of foodgrain traders held under the auspices of the All India Federation of Foodgrain Dealers Association at New Delhi.

The objective of Government policy is to assure to the producer the price announced by the Government for important cereals and an economic and remunerative price in regard to all important foodgrains and also to avoid the exploitation of the producer and the consumer by middlemen. To ensure this, State trading by public agencies has already been extended to cover a fairly significant portion of the marketable surplus in the country. Public agencies like the Food Corporation of India, the State Governments and the co-operatives are

[Shri Anna Sahib Shinde]

already procuring and distributing foodgrains through the public distribution system and are thus protecting both the intersts of the producer and the consumer. Expansion of the scope of State trading by the public sector agencies is considered by Government in the light of the situation prevailing from time to time.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : यह ठीक है कि कंज्यूमर और प्रोडयूसर का हित प्रमुख है। व्यापारी जो बीच में आता है उसका हित होता है या नहीं होता है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं जाता हूं। परन्तु जो पालिसी गवनमेंट ने अपनाई है उससे उनका हित होगा या नहीं, यह मुख्य चीज है। अब तक गवनमेंट की जो पालिसीं रही है उस में दो तीन बातें प्रमुख रही हैं। पहली बात तो मूल्यों के निर्धारण की है। मूल्य प्रोडयूसर को उसी अवस्था में मिल सकता है जब मार्किट में कम्पीटीशन हो। गवर्नमेंट जब अपनी ओर से मूल्यों का निर्धारण करती है तो दूसरी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते समय तो कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखती है लेकिन जब किसान के अनाज का मूल्य निर्धारण करती है तो किसान के कास्ट आफ प्रोडक्शन को वह बिल्कुल नहीं देखती है, उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारित कर देती है। इसलिए जब गवरमेंट राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने जा रही है तो किस तरह से किसान को उसकी फसल का ठीक मूल्य मिल सकेगा, क्या इसको भी वह देखेगी और क्या इसका संरक्षण भी वह करेगी ? गवर्नमेंट की ओर से अपनी खरीददारी की एजंसी होती है और गवर्नमेंट यह देखती है कि एक निश्चित भाव से कम पर व्यापारी अनाज खरीद न सकें। मैं तो देहात का आदमी हूं। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट की खरीददारी का सिस्टम क्या है। गवर्नमेंट ने अपने सैंटर्ज किसानों के लिए खोल रखे हैं जहां वह खरीददारी करती है। बेचारे किसान गाड़ियों में अनाज लाकर लाइनें बना कर खड़े रहते हैं, एक एक मील लम्बी लाइन लग जाती है लेकिन खरीददारी करने वाले सो रहे होते हैं, आराम से चाय पीते रहते हैं। खरीददारी करने वाला वहां कोई होता नहीं है। फिर कैटेगरी का चक्कर होता है, कैटेगरी एक, कैटेगरी दो वगैरह इसमें भी किसान को आपने फंसा दिया है। एक का एक दाम और दूसरे का दूसरा दाम। फिर यह भी षडयंत्र है कि इस में से घूल छनवाओ या उसको कहा जाता है कि आधा किलो अनाज फी मन घूल का निकालो। इस प्रकार से किसान की लूट हो रही है। अब जब अनाज खरीद लिया गया तो उसके स्टोरेज का प्रश्न पैदा हुआ। उसका भी इंतजाम आपके पास नहीं है। फिर वितरण का सवाल आता है। व्हाइट मैक्सीकन की जगह रेड और रेड की जगह व्हाइट भेज दिया जाता है और जहां से आर्डर्ज आए होते हैं उनको भेजा ही नहीं जाता है। स्टेट्स को इन्होंने भिखमंगा बना दिया है।

अगर अनाज की कमी हो तो उक्त अवस्था में गवर्नमेंट अजान की खरीददारी को कंट्रोल करे, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन गवर्नमेंट स्वीकार करती है कि अजान की बम्पर क्राप आ रही है। 1971 के बाद पी एल 480 का अनाज भी वह नहीं मंगायेंगी। ऐसी अवस्था में गवर्नमेंट ने खाद्य निगम के द्वारा अनाज खरीदने की आवश्यकता को क्यों अनुभव किया है ?

मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। गवर्नमेंट खाद्य निगम द्वारा खरीदने की जब बात करती है या राष्ट्रीयकरण की बात सोचती है तो क्या गवर्नमेंट के पास देश का सारा अनाज का स्टाक खरीद कर रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था है?

क्या गवर्नमेंट के पास चार हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था है जो समस्त अनाज को खरीदने के लिए आवश्यक होंगे ?

अगर ये दोनों व्यवस्थायें नहीं हैं तो आपने यह नीति क्यों अपनाई है ?

आपने खाद्य निगम के द्वारा गेहूं खरीदने की बात शुरू की है तो आज देश में जो करोड़ों आदमी अनाज का व्यापार करते हैं और वे जो बेकार हो जायेंगे तो उनको रिहैबिलिटेट करने का भी आपने कोई प्रबन्ध कर लिया है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस के पीछे कोई राजनीतिक षडयंत्र तो नहीं है ? अनाज की दृष्टि से जो डिफिसिट स्टेटस हैं उनको अपने चंगुल में लाने के लिए, उनको अपनी पार्टीबाजी का खिलोना बनाने के लिए क्या आप इस प्रकार का षडयंत्र तो नहीं कर रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है। शायद उन्होंने यह प्रश्न किसी गलतफहमी में किया है। असल में कोई नई नीति नहीं बनाई गई है। नीति वही चल रही है जिस पर सदन में काफी बहस हो चुकी है और जिस को सदन ने स्वीकार किया था। इसलिए नई नीति का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

यह प्रश्न क्यों उठाया गया है ? थोड़े से अनाज के व्यापारी दिल्ली में मिले, कुछ बिजली की बत्तियाँ जलाई गई, कुछ प्रस्ताव पास किये गये.... (**इंटरप्शंज**)

श्री मीठालाल मीना (सवाई माधोपुर): इस तरह से क्या व्यापारियों के बारे में मंत्री महोदय को बोलना चाहिये....

श्री स०मो बनर्जी (कानपुर) व्यापारी दाम बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री राम कृष्ण गुप्त (हिसार) : हिसार में भी जलाई गई थीं जब मंत्री महोदय गए थे।

श्री जगजीवन राम: मैं नहीं समझता हूं कि इस में इस तरह से घबरा जाने की कोई बात है। मैंने यही कहा है कि वहाँ मिले, बत्तियाँ जलाई गई, दीवाली मनाई गई, कुछ प्रस्ताव पास किये गये। मैं नहीं समझता था कि वे प्रस्ताव इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस सदन में उन पर चर्चा हो। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि इस में कोई नई नीति नहीं है।

माननीय सदस्य ने जानकारी न होने की वजह से अगर अंतिम प्रश्न पूछा है या उसको पैदा किया है....

श्री ओम प्रकाश त्यागी : असली वही है।

श्री जगजीवन राम : उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि किसानों को हम लूटना चाहते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत सहानुभूति प्रकट की है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हम ने कोई रुकावट नहीं डाली है गवर्नमेंट की नीति को उनको समझना चाहिये। अगर किसान को 76 रुपये से ज्यादा गेहूं के लिए कोई खरीददार मिल रहा हो तो हम किसी किसान को मजबूर नहीं करते हैं कि वह आ कर गवर्नमैंट को 76 रुपये में बेचे।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : कंट्रोल भी लगाया हुआ था।

श्री जगजीवन राम : सुनना चाहिये। राजनीतिक लाभ की बात नहीं करनी चाहिये। वस्तुस्थित को समझना चाहिये। हमने किसी किसान को मजबूर नहीं किया है। किसान को बराबर छूट है। इसी तरह व्यापारियों को भी बराबर छूट है कि वे 76 रुपये प्रति-क्विंटल से ऊपर जितना भी अनाज खरीदना चाहें, वे खरीद सकते हैं। हमने यह प्रबन्ध इसलिए किया है कि पिछले साल का हम को यह अनुभव रहा है कि अगर हम बाजार में नहीं रहते, तो किसानों का इतना बड़ा शोषण किया गया होता कि उनको 76 रुपये के बदले 60 रुपया दिया गया होता। मुझे खेद है कि व्यापारी वर्ग के लिए इस तरह वकालत की जाये, जिससे किसानों के हित पर कुठाराघात हो सकता है।

मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो कुछ हम ने किया है, वह सिर्फ किसानों के हित में किया है—इस दृष्टि से किया है कि अगर उन को व्यापारियों से 76 रुपये से कम मिलता है, तो हम वहाँ पर मौजूद हैं; किसान जितना भी गल्ला दें, अपनी एजेन्सीज के जरिये 76 रुपये पर उसको खरीदने के लिए तैयार हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी: और बेचेंगे कितने पर ? 76 रुपये से खरीद कर 95 रुपये पर। यह फ्राड है।

श्री जगजीवन राम : जो कोई फ्राड ही देखना चाहता है, उसको सचाई कहाँ नजर आती है ? लेकिन मैं सचाई बता रहा हूं।

यह कहा जा रहा है कि हम यह इन्तजाम करके व्यापारियों को काम से हटा रहे हैं। उन को हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सदन को मालूम है कि व्यापारी तो मुनाफे के लिए व्यापार करता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ अनाज की सब से अधिक आवश्यकता है, वह वहाँ अनाज भेजे, बल्कि वह वहाँ अनाज भेजना चाहता है, जहाँ उसको सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन हमें वहाँ अनाज भेजना पड़ता है, जहाँ अनाज की

[श्री जगजीवन राम]

सब से ज्यादा आवश्यकता होती है। सरकार, फूड कार्पोरेशन और कोआपरेटिव्ज द्वारा अनाज खरीदे जाने में यह एक मौलिक अन्तर है। मुझे आशा है कि सदन इस बात को समझेगा कि ऐसी व्यवस्था करना उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हित में आवश्यक है, ताकि उनका शोषण न किया जा सके, और सदन का बहुमत इस बारे में हमको अपना समर्थन देगा।

जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि हम कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं, सदन को उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमको सेल्ज-टैक्स देना होता है और मंडी के चार्जिज भी लगते हैं। शायद माननीय सदस्य को यह पता नहीं है और या वह जान-बूझ कर इस को नजर-अंदाज करना चाहते हैं, ताकि वह फूड कार्पोरेशन को बदनाम करें, जिस से व्यापारियों को शोषण का पूरा अवसर मिले। हम इस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह चाल नहीं चलेगी। इसके अलावा बोरे का दाम लगता है। मैं किसी भी वक्त इस बारे में सदन को पूरा ब्यौरा दे सकता हूं इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। बोरे का दाम, सेल्ज, टैक्स, मंडी के चार्जिज लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिज लगते हैं, गोडाउन के चार्ज लगते हैं, कैपिटल का इन्ट्रेस्ट लगता है और ट्रांसपोर्ट पर खर्चा होता है। व्यापारी शायद इस सब के बिना भी काम कर सकता है। कुछ व्यापारी तो सेल्ज-टैक्स भी गायब कर सकते हैं। मैं यह करने की क्षमता नहीं रखता हूं। (**व्यवधान**)

हमको इतना व्यापार करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। अगर फूड कार्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स और कोआपरेटिव्ज तीन, चार, पाँच सौ करोड़ रुपये की पूंजी का इन्तजाम नहीं कर सकेगी, तो फिर व्यापारी कहाँ से करेगा ?

जहाँ तक गोडाउन्ज का सवाल है, हमने यह इन्तजाम कर लिया है कि हम फूड कार्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और कोआपरेटिव्ज के जरिये जितना परचेज करेंगे, खरीदेंगे उसको सुरक्षित भंडार में रख सकें। हमने जो कुछ इन्तजाम किया है, वह उत्पादक और उपभोक्ता के हित में किया है।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh): The hon. Minister has tried to excite the sentiments of the House rather than deal with the problem from the economic aspect. 20,000 representatives of the dealers in foodgrains collected at Delhi recently. They were not monopolists ; the whole trade is not concentrated in a few hands. Millions of people throughout the country are dealing in foodgrains. Therefore the question is what was the apprehension in their mind. The hon. Minister also happens to be the President of the ruling party which adopted a resolution at Bombay wherein it was said that wholesale trade in foodgrains would be nationalised.

I want to ask whether it is a step towards finishing monopoly or whether it is just raising a political issue in order to get the sympathy of the common man.

Shri Piloo Mody (Godhra) : Creating a State monopoly.

Shri Shri Chand Goyal : Here it is the question of the interest of millions of people who are engaged in this trade. You have also to protect and safeguard their interests along with the interest of the consumers and of the producers. When the Government decides upon a policy, fixes the rates of a particular commodity, enters the market and says that if prices fall below this particular level, Government will perchance procure it at that price. Then where is the occasion for exploitation of the farmers by the traders ? After the Government entered as a competitor and resorted to the procurement policy, such occasions have not arisen at all. Now that the hon. Minister has been claiming that in a few years we will be in a position to export foodgrains to other countries because of the green revolution and there is no shortage, where was the necessity for adopting a resolution ?

This statement says absolutely nothing ; it is just an attempt to hide information. I want to know from him as President of the party and also as Food Minister whether Government has a mind to implement the resolution which was adopted at Bombay to nationalise the wholesale trade in foodgrains. Government has not given out its mind and the traders collected here because they apprehended the implementation of that resolution. We do not mind if the Government enters the market as a competitor

and fixes the prices, which will be in the interest of the producer. We welcome that step. But when you want to displace these millions of people by nationalising the wholesale trade, have you not to safeguard their interest ? Are they not your people ? Can you not bring some curbs on their activities through regulatory measures and control the few exploiters that may be there ?

It is estimated that Government will have to invest about Rs.1,800 crores in this project if it assumes control of the entire wholesale trade in foodgrains. Will it be worth while to invest Rs.1,800 crores in the distributing system rather than investing the same in production so that we increse our production to such an extent that these things will become absolutely outdated ?

I would also like to know whether Government has applied its mind as to what means of livelihood it will provide to the millions of people who are engaged in this trade and whether Government feels that there is enough scope for Government as well as for the business community to go side by side in competition because competition alone ensures the safeguarding of the interests of the producer, the consumer and the business community.

Shri Jagjiwan Ram : Sir, the hon. Member has presumed many things. I do not know whether it is out of ignorance or it is deliberate. When there is a surplus or there is plenty in the country, unfortunately, up till now. the experience of the Indian farmer has been that during the year he produces more, he will get less price. In the past few years, I have assured the Indian farmer that even during the year he produces more, the prices will not be permitted to fall. I have no doubt that if it was left entirely to the trade channels, the prices could have crashed even this year. Even the traders will agree.

Then, a point was raised about capital. I have to put a question : If the Government cannot manage this amount of capital, wherefrom the private trade will manage it ?

Shri Shri Chand Goyal : They are thousands in number.

Shri Jagjiwan Ram : I know their number. I do not think they will have the capacity, and to get that much amount of advances from the banks to manage it. It will be impossible for the traders to manage it. I have not squeezed out the traders from retail sale. Again, it comes out of some wrong presumption or wrong briefing or wrong apprehension.

Now, he asked, when is the Government going to implement it ? The Government is implementing it. There is no question of that. We are implementing it. We have indicated in the reply itself that whereever an occasion arises and the situation so requires, we will exclude the activity of the public sector in the food trade. More than that I am not going to say. I have not excluded the traders from retail sale. A few hundred thousands are there. When one has to take care of millions, certainly, the interest of millions is greater than the interest of a few hundred thousands.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि व्यापारी व्यापार करते हैं मुनाफा कमाने के लिये, अगर सीमित मुनाफा कमाने के लिये करते तो ज्यादा आपत्ति नहीं होती, लेकिन वे मुनाफाखोरी करने के लिये करते हैं और इन का यह भी कहना है कि सरकार जो व्यापार करती है वह लोक-कल्याण के लिये करती है। लेकिन यह भी सही नहीं है आज की स्थिति में। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—यह मिलाजुला मामला वे छोड़ दें, हम तो इस राय के हैं और सरकारी पार्टी ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पास किया है। सरकार बताये—क्या निश्चित अवधि में अनाज का पूरा थोक व्यापार सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ले लेगी तथा इस वक्त सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के द्वारा कितने टन अनाज खरीदा जाता है तथा वितरित किया जाता है—इस के आंकड़े भी वे दें— और अनाज व्यापारियों के द्वारा कितना किया जा रहा है, उसके आंकड़े भी दें ?

एक सवाल यहां पर उठाया गया है—किसानों को आप क्या दाम देते हैं और उपभोक्ताओं को किस दाम पर बेचते हैं—इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों और विभिन्न जगहों के आंकड़े दें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि

हम सेल्ज टैक्स देते हैं या अमुक खर्च पड़ते हैं। आम तौर पर अर्थशास्त्रज्ञों की यह राय है कि सरकारी वितरण का इन्तजाम इतना अकार्यक्षम और खर्चीला है, कि उसके चलते किसानों को पर्याप्त फायदा नहीं होता है तथा उपभोक्ताओं का नुकसान होता है। जैसे व्यापारी लोग मुनाफाखोरी करते हैं, आप के व्यापार में भी यह दोष है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह की जानकारी सदन को देगी कि कितनी अवधि के अन्दर थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा, इस वक्त कितने अंश का वह राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं और किसानों को जो दाम मिलता है और उपभोक्ताओं को जिस दाम पर बेचते हैं– उसमें विभिन्न स्थानों में क्या फर्क है ?

इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं–अभी मंत्री महोदय ने कहा, जब किसान अतिरिक्त अनाज उत्पादन करता है, तो दाम गिरने लगते हैं, उसका शोषण होने लगता है, उससे सरकार ने उस को बचाया है। लेकिन इसी सदन में दो साल पहले कई बार चर्चायें उठाई गई हैं कि आप का फूड कारपोरेशन और सरकारी संस्थायें, जिस मात्रा में उनको किसान का अनाज खरीदना चाहिये और समय में खरीदना चाहिये, वह नहीं कर रहीं हैं, इससे माल पड़ा रहा और सड़ गया। क्या इसके बारे में मंत्री महोदय सफाई देंगे और सदन को आश्वासित करेंगे कि किसानों को न केवल सही दाम मिलेंगे बल्कि समय पर अनाज खरीदने के लिये भी सरकार आगे आयेगी? आज जो जिला बन्दी और प्रान्त बन्दी की व्यवस्था की जाती है, उसको लेकर परमिट वगैरह देते समय पैसा खाने का काम सरकारी अफसरों के द्वारा किया जाता है, इस के बारे में भी कोई ठोस आश्वासन मंत्री महोदय दें, तो अच्छा होगा।

श्री जगजीवन राम: अध्यक्ष महोदय, जब हम अनाज की बात करते हैं, तो यह समझ लेना चाहिये कि कुछ मुख्य अनाज के सम्बन्ध में ही बात करते हैं, वरना हमारे देश में कई दर्जन किस्म के अनाज होते हैं, कई बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, कुछ कम होते हैं। लेकिन यही एक देश है जहाँ इतनी संख्या में फूडग्रेन्ज होते है, दूसरे किसी मुल्क में इतने नहीं होते हैं। जब हम फूड ग्रेन्ज की बात करते हैं तो मुख्यतः खाद्यान्नों के सम्बन्ध में बात करते हैं।

अब जहाँ तक थोक व्यापार को सम्पूर्ण देश में सरकारी क्षेत्र में कर लेंगे–मैं यहाँ इस बात को साफ कर देना चाहता हूं–सभी अनाजों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की मंशा नहीं है....

श्री मधु लिमये: किन अनाजों को करेंगे, यह बतला दीजिए।

श्री जगजीवन राम: सुन लीजिये। बम्बई के जिस प्रस्ताव का उद्धरण दे कर यहाँ पर जिक्र किया गया है, उस प्रस्ताव के पढ़ने से यह भी साफ हो जाता है कि होल-सेल का राष्ट्रीयकरण करने की मंशा क्या है। उस मंशा के लिये करना है, होल-सेल का राष्ट्रीयकरण करने के लिये ही राष्ट्रीयकरण नहीं करना है, हमारे कुछ लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं, उनको सामने रख कर ही राष्ट्रीयकरण करना है और जैसा कि मैंने बतलाया है–इसमें दो मुख्य लक्ष्य हैं–एक तो हम किसानों को उचित दाम दिला सकें और दूसरे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बेच सकें। इन दो मुख्य उद्देश्यों को सामने रख कर जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी कि थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाय, वहाँ पर किया जायगा और जहाँ जहाँ करना था, वहाँ कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने जिला बन्दी और प्रान्त बन्दी का उल्लेख किया––उनको महाराष्ट्र का तजुर्बा है, ऐसा महाराष्ट्र में है, और कहीं नहीं है।

दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि कितने दाम पर खरीदते हैं और कितने पर देते हैं। सदन को मालूम है कि अभी किसानों से 76 रु० प्रति क्विंटल पर लिया जाता है और हमारी ईशू प्राइस राज्य सरकारों को 78 रु० है....

श्री मधु लिमये: राज्य सरकारों को छोड़िये, उपभोक्ताओं का बतलाइये ?

श्री जगजीवन राम: उपभोक्ताओं का ही बता रहा हूं। मैंने अभी गेहूं के बारे में बतलाया है कि 78 रु० में देते हैं, इसमें 4 से 8 रु० और लगा कर उपभोक्ताओं को देते हैं। इस पर जितना हमारा खर्च आ रहा है, वह पूरा प्राप्त नहीं हो रहा है....

श्री ओम प्रकाश त्यागी : दिल्ली सरकार को 95 रुपये में बेचने का आदेश दिया था। 76 रु० का गेहूं 95 रु० में। जब उन्होंने इसके बारे में बहस की तो 81 रु० में तय हुआ। ऐसा हुआ या नहीं ?

श्री जगजीवन राम : थोड़ा उस के फर्क को समझ कर सम्पूर्ण सत्य को कहना चाहिये। वह सफेद गेहूं का दाम था, सब का नहीं था। 8 रु० तो इस का स्टेशन तक ही खर्च लगता है। इस चीज को मैं सदन के सामने रख दूंगा—यह ऐसी चीज है जिसको सदन को देखना चाहिए कि कहां पर ज्यादा खर्च होता है। हम बराबर कोशिश करते हैं कि जितना खर्च हो कम हो, फिर भी हम चाहेंगे कि सदन इसको देखे और बतावे कि इसमें और कहां कमी की जा सकती है.....

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सफेद गेहूं का भाव क्या है ?

श्री जगजीवन राम : पिछले साल 76 रु० था। दूसरे का भी 76 रु० था।

श्री राम सेवक यादव : फिर दोनों के खरीदने और बेचने का भाव अलग अलग क्यों है ?

श्री जगजीवन राम : इसलिये होता है कि जहां पर घाटा होता है, उस घाटे को पूरा करने की भी आवश्यकता है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, सदन को मालूम है....

13.00 hrs.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अभी भी गोदामों में बड़ा घाटा होता है।

श्री जगजीवन राम : मैंने बताया है कि गोदामों की जहां कमी थी, उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। कितना फूड कारपोरेशन की तरफ से खरीदा और कितना कैसे खरीदा-ये आंकड़े हम सदन में रखवा देंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या इस बार आप विश्वास दिलाते हैं कि इससे नीचे कीमत गिरने नहीं दी जायेगी और जितना भी अनाज आवेगा वह समय पर खरीदा जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : मैं विश्वास दिलाता हूं और पिछले साल भी सारा अनाज खरीदा था। लेकिन पिछले साल एक बात हो गई थी कि गेहूं में कुछ बीमारी लग गई थी। लेकिन जो दाम हमने निश्चित किये हैं वह अच्छे गेहूं के दाम निश्चित किए हैं इसलिए जो गेहूं हमारे पास आ रहा है वह अच्छा गेहूं है या नहीं। यह भी देखना पड़ेगा कि जो गेहूं आ रहा है उसमें मिलावट तो नहीं है या उसमें ज्यादा धूल और कंकड़ तो नहीं हैं। ...

श्री कंवर लाल गुप्त : लेकिन खरीदा सब जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : सब खरीदा जायेगा।

श्री मधु लिमये : मैंने सभी अनाजों के बारे में नहीं पूछा है। मैंने पांच प्रमुख अनाजों के बारे में कहा कि कितने अनाज का राष्ट्रीय-करण कर चुके हैं और कितनी अवधि में करने वाले हैं जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मकई है।

श्री जगजीवन राम : मैंने कहा है कि इसके आंकड़े सदन को बता दूंगा।

13.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Mr. Speaker : Shri F. A. Ahmed.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh) : On behalf of Shri F. A. Ahmed, I beg to lay on the Table. ...

Shri Srinibas Misra (Cuttack) : Sir, I rise on a point of order.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा कहना यह है कि इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए और वह इसलिए कि जो सरकार की घोषित नीति है उसके विपरीत ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं प्रीवी पर्स के बारे में। तो ऐसी हालत में सदन की कार्यवाही चलेगी कैसे ? जब सरकार के मन्त्री ही सरकार द्वारा घोषित नीति को खत्म करने का प्रयास करेंगे प्रधान मन्त्री के आशीर्वाद से, तो फिर सरकार कैसे चलेगी ?